(ग) 31-10-1994 की स्थिति के अनुसार पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास मध्य प्रदेश के रायसेन और विदिशा जिलों से संबंधित कोई सिंचाई परियोजना प्रस्ताव लंबित नहीं था ।

Devices installed at Thermal Power Plants

1105. SHRI JAGMOHAN: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether about 2000 metric tons of pollutants are injected into the atmosphere of Delhi everyday;

(b) whether 16 per cent of these pollutants are contributed by the two thermal power plants, namely, Badarpur and Indraprastha Power Plants;

(c) whether thee pollution control devices installed in the two aforesaid power plants are inadequate, ineffective and inefficient; and

(d) what measures are being taken to eliminate pollutants totally, from two power plants?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Yes, Sir. Major sources of air pollution in Delhi are vehicles, theremal power plants, industries and domestic coal burnings. It is estimated that 2,000 metric tonnes of pollutants are emitted into the atmosphere everyday.

(b) 18 per cent of the pollution load is contributed by thermal power plants which include Badarpur and Indraprastha plants.

(c) Badarpur and Indraprastha Thermal Power Plants have installed high efficiency electrostatic precipitators. Sometimes, due to operation and maintenance problems these units do not comply with the prescribed SPM limits of 150 mg/m3.

(d) Authorities of these power plants have been advised to operate and maintain the electrostatic precipitators effectively to comply with the standards prescribed by the Government.

वन भूमि का आबंटन

1106. **श्री नागमणि :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर, 1994 के दैनिक "जनसत्ता" में "जंगलों की जमीन उद्योगपतियों को देने का देशभर में विरोध होगा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा "वन विधेयक" का प्रारूप तैयार किया गया है जो उद्योगपतियों के हित में है ;

(ग) क्या प्रस्तावित प्रारूप में देश के भूमिहीन परिवारों को वनारोपण हेतु वन भूमि पट्टे पर देने तथा भूमिहीन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में कोई प्रावधान है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय वन अधिनियम, 1927 की जगह लाये जाने वाले प्रस्तावित विधान के प्रारूप में उद्योगपतियों के बारे में कोई उपबंध शामिल नहीं है तथापि देश में अवक्रमित वन भूमि की काफी मात्रा में अवैध कब्जे के बढ़ते खतरे तथा हरित क्षेत्र के विस्तार के लिये इस पर अवश्यक रूप से वनीकरण करने की आवश्यकता, अवैध कब्जे को रोकने तथा मृदा-अनाच्छादन के रूकाव तथा ईधन एवं चारे की आवश्यकता को भी पूरा करने के लिये तथा इसके द्वारा वर्तमान प्राकृतिक वनों पर भार को कम करने और संरक्षित क्षेत्रों

को दृष्टि में रखते हुये, सरकार बुरी तरह अवक्रमित क्षेत्रों के वनीकरण के लिये, राज्य वन विकास निगमों की भागीदारी के साथ उद्योगों को शामिल करने पर विचार कर रही है जिससे केन्द्र एवं राज्य सरकारें, गैर सरकारी संगठनों तथा सार्वजनिक सहकारिता की वनीकरण की स्कीमों के लिये प्रयासों में वृद्धि एवं क्षेत्रीय संसाधन उपलब्ध हो सकें। विचाराधीन स्कीमों को, इसमें शामिल विभिन्न मुद्दों के ध्यानपूर्वक मूल्यांकन तथा परम्परागत अधिकारों के संरक्षण एवं ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों द्वारा ली जा रही छूटों को सुनिश्चित करने के बाद ही अंतिम रूप दिया जायेगा। जैसी की कल्पना की गई है, इस स्कीम का उद्देश्य बायोमास की उपलब्धता, ईंधन की लकड़ी तथा चारे में वृद्धि करके, ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों को लाभ प्रदान करना तथा ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करने के लिये रास्ते खोलना भी है।

(ग) से (ङ) भारतीय वन अधिनियम, 1927 की जगह लेने वाला विधान, जो विचाराधीन है, में "वन ग्राम" बनाये जाने की व्यवस्था है, जिसका प्रबंध ग्राम समुदाय के स्थानीय प्रतिनिधि निकाय द्वारा किया जायेगा। वन ग्राम तथा अन्य सार्वजनिक भूमि (सुरक्षित एवं संरक्षित वनों के अतिरिक्त) का, पृथक पृथक लोगों पर अधिमानतः संबंधित गांव के भूमिहीनों, सीमांत एवं छोट किसानों को, संरक्षण एवं वनीकरण के लिये, भोगाधिकार में हिस्सेदारी के बदले, हिस्सा निर्धारण करने का प्रावधान किया गया है।

UN Report on Child Labour

1107. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a new UN Report on Child Labour says that young children from India are still being sold as jockeys for Camel racing in the Gulf States or as young brides to older men of Saudi Arabia, as per a newspaper report in the 'Hindustan Times' dated 21st November, 1994, entitled "Indian Kids sold in the Gulf"

(b) if so, what are the facts in this regard; and

(c) what action Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): (a) and (b) Yes, Madam. Attention of the Government has been drawn to the interim report submitted by the Special Reporter on Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography appointed by the UN Commission of Human Rights. The report inter-alia touches on a range of issues relating to child labour, exploitation and abuse of children, abduction, use of child jockeys for camel racing and the practice of young child Brides from India and other South Asian countries being married to older men in Saudi Arabia. The report is not specific to India but deals with these issues and problems in a regional perspective and refers to the situation in other countries as well, apart from India.

(c) Government have already taken necessary steps to sensitise officers of the police department to take immediate legal action whenever such incidents come to their notice. In order to check this practice, immigration authorities have been directed to be more vigilant while scrutinnsing the travel documents of the persons (including Indians) accompanying such minor children and/or minor brides at the immigration check points.

Review of treaties with Nepal

1108. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are considering to review the 1950 treaty of peace and friendship and other agreements in the areas of water resources trade and transit, commerce with the new Government of Nepal;

(b) whether the 1950 treaty is heavily weighted in favour of Nepal;